Parimal Nathwani
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member:
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Commerce and Industry
Permanent Special Invitee:
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: 011-23794010
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

' Vraj ', Opp. HDFC Bank,
Beside Chandanbala Tower,
Nr. Suvidha Shopping Centre,
Paldi, Ahmedabad - 380 007

मीडिया रीलिज

झारखण्ड में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में विलम्बः भूमि अधिग्रहण एक समस्या

राज्य सभा में कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रीजी का सांसद श्री नथवाणीजी को उत्तर

अगस्त 17, 2010 : जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झारखण्ड में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत नौ सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओ को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मॉनीटर किया जाता है , ताकि किसानों को शीक्र लाभ मिल सके। केन्द्रीय कोयला तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के राज्य मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने राज्य सभा में सांसद श्री परिमल नथवाणी को एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया।

मंत्री महोदय द्वारा इन नौ परियोजनाओं की सदन के पटल पर रखी गई जानकारी के मुताबिक, कांसजोर, सोनुआ, सुरांगी, अपर शंख, और पंचखेरो परियोजनाएं फिलहाल चल रही हैं; जब कि लतरातू और टपकारा जलाशय परियोजनाएं वर्ष 2002-03 में पूर्ण हो चुकी हैं। तोरई परियोजना वर्तमान मे आस्थगित है।

गुमानी, सोनुआ और अपर शंख परियोजना में भूमि अधिग्रहण संबधी समस्याएं है। कांसजोर परियोजना मे बैराज, गेट्स, स्टोप-लोग्स के डिजाइन तथा ड्रांईग्स के अनुमोदन और स्थापना कार्य में विलंब हुआ है । सुरांगी परियोजना में नहर के इलाइनमेंट में परिवर्तन के लिए स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण में बाधा पहुंचाई जा रही है । पंचखेरो परियोजना में भी स्थानीय लोंगो द्वारा निर्माण में बाधा पहुंचाई जा रही है।

इन तमाम विलम्बित सिंचाई परियोजनाओं की अनुमानित लागत कुल रु. 570.61 करोड़ है। अगस्त 8, 2010 तक इन परियोजनाओं के लिए कुल रु. 102.94 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई । अपर शंख और पंचखेरो परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत वर्ष 2004-05 में शामिल किया गया जब कि शेष तमाम परियोजनाओं को वर्ष 1997-98 में ए.आई.बी.पी. में शामिल किया गया था।

श्री नथवाणीजी ने झारखण्ड में निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा भी मांगा था जिसके उत्तर में मंत्रीजी ने यह बताया कि झारखण्ड राज्य में इस समय कोई विद्युत परियोजना कार्यान्वयन अधीन नहीं है।

★ ★ ★